ShodhSamajik: Journal of Social Studies
January-June 2026 3(1)
https://shodhsamajik.com/

Original Article

ALCOHOL BAN AND POPULIST POLICIES: NEW DIMENSIONS OF WOMEN'S POLITICS IN BIHAR

शराबबंदी और लोक-लुभावन नीतियां : बिहार में महिला राजनीति के नए आयाम

Dr. Ravi Kant Pandey [1*]
[1] Assistant Professor, Department of Political Science A.S. College, Bikramganj Rohtas, Bihar, India

ABSTRACT

English: This research paper focuses on the changing role and electoral behavior of women in contemporary Bihar politics. Traditionally, Bihar's politics has revolved around caste equations, but in the last two decades, 'gender' has emerged as an independent and decisive political category. The main objective of this research is to analyze how the liquor ban (2016) and other populist policies implemented by the Nitish Kumar government (such as the Chief Minister's Bicycle Scheme and the Jeevika Mission) have transformed women voters into an organized 'vote bank'.
Using qualitative and quantitative methods, the paper explores how these policies have not only increased women's voter turnout but also strengthened their political consciousness and agency. Data analysis clearly indicates that women voting in greater numbers than men signals the emergence of a new 'silent voter' in Bihar. In conclusion, this paper argues that policies like the liquor ban have established a new 'social contract' between the state and its female citizens, alongside social reform, although the challenges and political limitations of its implementation also require reconsideration.

Hindi: प्रस्तुत शोध पत्र बिहार की समकालीन राजनीति में महिलाओं की बदलती भूमिका और चुनावी व्यवहार पर केंद्रित है। पारंपरिक रूप से बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, किंतु पिछले दो दशकों में 'लिंग' (Gender) एक स्वतंत्र और निर्णायक राजनीतिक श्रेणी के रूप में उभरा है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि नीतीश कुमार सरकार द्वारा लागू की गई 'शराबबंदी' (2016) और अन्य लोक-लुभावन नीतियों (जैसे मुख्यमंत्री साइकिल योजना और जीविका मिशन) ने महिला मतदाताओं को किस प्रकार एक संगठित 'वोट बैंक' में परिवर्तित किया है।
शोध पत्र में गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करते हुए यह पड़ताल की गई है कि इन नीतियों ने न केवल महिलाओं की मतदान भागीदारी (Voter Turnout) को बढ़ाया है, बल्कि उनकी राजनीतिक चेतना और 'एजेंसी' को भी मजबूती प्रदान की है। डेटा विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं का पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान करना बिहार में एक नए 'साइलेंट वोटर' के उदय का संकेत है। निष्कर्षतः, यह पेपर तर्क देता है कि शराबबंदी जैसी नीतियों ने सामाजिक सुधार के साथ-साथ राज्य और महिला नागरिक के बीच एक नया 'सामाजिक अनुबंध' (Social Contract) स्थापित किया है, हालांकि इसके कार्यान्वयन की चुनौतियां और राजनीतिक सीमाओं पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है।

Keywords: Bihar Politics, Liquor Ban, Women's Empowerment, Populism, Voting Behavior, Jeevika Mission, Silent Voter बिहार राजनीति, शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण, लोक-लुभावनवाद (Populism), मतदान व्यवहार, जीविका मिशन, साइलेंट वोटर

*Corresponding Author:
Email address: Dr. Ravi Kant Pandey (ravikantP829@gmail.com)

Received: 06 November 2025; **Accepted:** 28 December 2025; **Published** 03 February 2026
DOI: 10.29121/ShodhSamajik.v3.i1.2026.72
Page Number: 31-38
Journal Title: ShodhSamajik: Journal of Social Studies
Journal Abbreviation: ShodhSamajik J. Soc. Stud.
Online ISSN: 3049-2319
Publisher: Granthaalayah Publications and Printers, India
Conflict of Interests: The authors declare that they have no competing interests.
Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
Authors' Contributions: Each author made an equal contribution to the conception and design of the study. All authors have reviewed and approved the final version of the manuscript for publication.
Transparency: The authors affirm that this manuscript presents an honest, accurate, and transparent account of the study. All essential aspects have been included, and any deviations from the original study plan have been clearly explained. The writing process strictly adhered to established ethical standards.

Copyright: © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

प्रस्तावना

बिहार की राजनीति ऐतिहासिक रूप से जातिगत पहचान और पितृसत्तात्मक संरचनाओं के प्रभाव में रही है, जहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण और चुनावी विमर्श अक्सर 'पहचान की राजनीति' (Identity Politics) के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा है Kumar et al. (2018)। हालांकि, पिछले दो दशकों में राज्य की राजनीतिक संस्कृति में एक गुणात्मक परिवर्तन देखा गया है, जिसे "लिंग-आधारित राजनीतिक लामबंदी" (Gender-based Political Mobilization) कहा जा सकता है। इस परिवर्तन का मुख्य आधार राज्य सरकार द्वारा लागू की गई लोक-लुभावन नीतियां (Populist Policies) और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम रहे हैं। इनमें से शराबबंदी (Liquor Prohibition) एक ऐसी मील का पत्थर नीति साबित हुई है, जिसने बिहार में महिलाओं को एक स्वतंत्र और मुखर 'वोट बैंक' के रूप में स्थापित कर दिया है Singh, et al. (2016), Zumbish, (2019)।

बिहार में महिला सशक्तिकरण की यह यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं रही है, बल्कि यह ठोस सांख्यिकीय प्रमाणों पर आधारित है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के आंकड़ों के अनुसार, हालिया विधानसभा चुनावों में महिलाओं की मतदान भागीदारी पुरुषों की तुलना में लगातार अधिक रही है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में जहाँ पुरुषों का मतदान प्रतिशत 59.39% था, वहीं महिलाओं ने 59.99% मतदान कर अपनी राजनीतिक सक्रियता दर्ज कराई Election Commission of India. (2020 & 2025)। यह प्रवृत्ति वर्ष 2025 के चुनाव आंकड़ों में और भी स्पष्ट होकर उभरी है, जहाँ महिला मतदान प्रतिशत 71.6% तक पहुँच गया, जो पुरुषों के 62.8% की तुलना में काफी अधिक है ECI Report (2025)। यह बढ़ता हुआ 'जेंडर गैप' (Gender Gap) इस बात का प्रमाण है कि बिहार की महिलाएं अब केवल अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के निर्देशों पर वोट नहीं दे रही हैं, बल्कि वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक चेतना विकसित कर चुकी हैं Datta et al. (2015), Pradhan et al. (2021)।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात किया, जिन्हें राजनीति विज्ञान की भाषा में 'लक्षित लोक-लुभावनवाद' (Targeted Populism) कहा जा सकता है। इनमें मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण (2006) और 'जीविका' (JEEViKA) जैसे स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना शामिल है World Bank. (2015/2024), Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS). (2025)। इन योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं के बीच एक नया आत्मविश्वास पैदा किया, जिससे वे सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनीं Kumar et al. (2018)। हालांकि, इन सभी के शीर्ष पर 'शराबबंदी' की नीति रही, जिसे मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर महिलाओं की मांग पर 1 अप्रैल 2016 को लागू किया था Hindustan (2021) ।

शराबबंदी को केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना जा सकता; यह एक सामाजिक प्रयोग था जिसने सीधे तौर पर घरेलू हिंसा, पारिवारिक अर्थव्यवस्था और महिलाओं की गरिमा को प्रभावित किया Ahmed et al. (2022), Sakshi et al. (2025)। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी के बाद बिहार में घरेलू हिंसा की घटनाओं में सापेक्षिक कमी दर्ज की गई है, जिसने महिलाओं के बीच राज्य की एक 'रक्षक' (Protector State) की छवि निर्मित की है Ideas for India. (2023)।

प्रस्तुत शोध पत्र इस आधारवाक्य (Hypothesis) की जांच करता है कि क्या बिहार में शराबबंदी और उससे जुड़ी लोक-लुभावन नीतियां महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, या ये केवल एक चुनावी रणनीति मात्र हैं? हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों और मतदान व्यवहार के विश्लेषण के माध्यम से, यह पेपर बिहार की राजनीति में उभरते 'महिला राजनीति के नए आयामों' को रेखांकित करने का प्रयास करता है।

साहित्य की समीक्षा (LITERATURE REVIEW)

बिहार में महिला राजनीति और शराबबंदी के प्रभाव पर उपलब्ध अकादमिक साहित्य को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1) महिला मतदाता और 'जेंडर गैप' का सिद्धांत

संजय कुमार (Kumar, 2018) ने अपनी पुस्तक 'Caste and Voting Behavior in Bihar' में तर्क दिया है कि बिहार में मतदान का स्वरूप अब केवल जाति आधारित नहीं रह गया है। उन्होंने 'जेंडर प्लस' (Gender Plus) फैक्टर की अवधारणा दी है, जिसमें महिलाएं जातिगत सीमाओं को लांघकर उन दलों को चुन रही हैं जो उनके जीवन की सुरक्षा और गरिमा की बात करते हैं। इसी क्रम में, मुक्ता साक्षी Sakshi et al. (2025) ने हालिया डेटा के आधार पर स्पष्ट किया है कि बिहार में 'महिला वोट बैंक' का उदय एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हुआ है, जिसे अब किसी पुरुष प्रधान परिवार की छाया मात्र नहीं माना जा सकता।

2) लोक-लुभावनवाद और 'रक्षक राज्य' (Protector State) की छवि

क्रिस्टोफ़ जाफ़रलॉट और वर्नोन Jaffrelot and Verniers (2020) के अनुसार, नीतीश कुमार ने "सबआल्टरन हिंदुत्व" और विकासवाद के बीच एक ऐसी जगह बनाई जहाँ महिलाएं उनकी मुख्य लाभार्थी बनीं। विश्व बैंक (2015) की रिपोर्ट 'Jeevika' परियोजना पर यह रेखांकित करती है कि स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी संगठित किया। कुमारी और झा Kumari and Jha (2018) का शोध बताता है कि साइकिल योजना जैसी 'लोक-लुभावन' नीतियों ने राज्य (State) और महिलाओं के बीच एक सीधा संवाद स्थापित किया, जिससे सरकार की छवि एक 'अभिभावक' या 'रक्षक' के रूप में बनी।

3) शराबबंदी: सामाजिक सुधार बनाम चुनावी रणनीति

शराबबंदी के प्रभाव पर सिन्हा Sinha et al. (2025) का अध्ययन महत्वपूर्ण है। वह तर्क देते हैं कि यह नीति नीतिगत से अधिक 'नैतिक' (Moral) थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की सहानुभूति बटोरना था। वहीं, अहमद Ahmed et al. (2022) ने अपने शोध में शराबबंदी के 'अंधेरे पक्ष' पर प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि जहाँ एक ओर इसने घरेलू हिंसा में कमी (NFHS-5 के अनुसार) की है, वहीं दूसरी ओर 'अवैध शराब अर्थव्यवस्था' और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने राज्य के

कानून व्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौतियां पेश की हैं। आइडियाज फॉर इंडिया (2023) के एक शोध लेख के अनुसार, शराबबंदी का सबसे सकारात्मक प्रभाव गरीब परिवारों की डिस्पोजेबल आय (Disposable Income) में वृद्धि और बच्चों की शिक्षा पर बढ़ते खर्च के रूप में देखा गया है।

4) हालिया चुनावों का प्रभाव विश्लेषण (2020-2025)

अंशुमान प्रधान Pradhan et al. (2021) ने 2020 के विधानसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हुए बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत में महिलाओं का निर्णायक हाथ था, जिन्होंने जंगलराज की यादों और शराबबंदी के समर्थन में मतदान किया। जुम्बिश Zumbish (2019) ने अपनी पुस्तक 'The Silent Revolution' में इस बात पर जोर दिया है कि बिहार की महिलाएं अब चुनावी घोषणापत्रों में 'शिक्षा' और 'सुरक्षा' के बजाय 'अधिकार' और 'प्रतिनिधित्व' की मांग करने लगी हैं, जो कि शराबबंदी के बाद उपजी राजनीतिक चेतना का ही परिणाम है।

शोध के उद्देश्य (RESEARCH OBJECTIVES)

प्रस्तुत शोध का मुख्य लक्ष्य बिहार में महिला सशक्तिकरण के नाम पर संचालित योजनाओं और उनके चुनावी परिणामों के बीच के गहरे अंतर्संबंधों को समझना है। इसके विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- **जीविका दीदियों की राजनीतिक भूमिका का विश्लेषण:** यह पता लगाना कि 'जीविका' (JEEViKA) समूहों के माध्यम से संगठित महिलाओं ने 2025 के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार एक संगठित वोट बैंक के रूप में कार्य किया।
- **आर्थिक प्रोत्साहन और मतदान व्यवहार:** 2025 चुनाव के दौरान जीविका दीदियों को दिए गए ₹10,000 के आर्थिक लाभ और स्नातक छात्राओं के प्रोत्साहन राशि (कन्या उत्थान योजना) के मतदान पैटर्न पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- **शराबबंदी का प्रभाव:** शराबबंदी की निरंतरता और महिलाओं के बीच नीतीश सरकार के प्रति अटूट 'निष्ठा' (Loyalty) के बीच के संबंधों की पड़ताल करना।
- **योजनाओं का चुनावी रूपांतरण:** यह समझना कि साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति जैसी पुरानी योजनाओं ने 2025 में 'प्रो-इंकंबेंसी' (Pro-incumbency) निर्मित करने में कितनी भूमिका निभाई।

शोध कार्यप्रणाली (RESEARCH METHODOLOGY)

प्रस्तुत शोध में मिश्रित पद्धति (Mixed-Methodology) का अवलंबन किया गया है, जो मात्रात्मक (Quantitative) डेटा की सटीकता और गुणात्मक (Qualitative) विश्लेषण की गहराई को जोड़ती है। यह शोध मुख्य रूप से 'डिस्क्रिप्टिव' (Descriptive) और 'एनालिटिकल' (Analytical) शोध प्रारूप पर आधारित है।

1) शोध का क्षेत्र (Area of Study)

शोध का कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार है, किंतु गहन अध्ययन के लिए उन जिलों को प्राथमिकता दी गई है जहाँ 'जीविका' (JEEViKA) समूहों की सघनता और महिला मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक रहा है। इसमें उत्तर बिहार (मुजफ्फरपुर, दरभंगा) और दक्षिण बिहार (गया, पटना ग्रामीण) के क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

2) प्रतिदर्श चयन और आकार (Sampling and Sample Size)

शोध की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए 'स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण' (Stratified Random Sampling) पद्धति का उपयोग किया गया है:

- **कुल सैंपल साइज (N):** बिहार के 10 चयनित जिलों से कुल 1,500 उत्तरदाताओं (Respondents) का चयन किया गया है।
- **श्रेणीबद्ध विभाजन:**

जीविका दीदियां (800): जिन्हें ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई।

स्नातक छात्राएं (400): जिन्हें 'कन्या उत्थान योजना' के तहत ₹50,000 की राशि प्राप्त हुई।

सामान्य महिला मतदाता (300): जो किसी भी प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ योजना से नहीं जुड़ी थीं (नियंत्रण समूह के रूप में)।

3) डेटा संग्रहण के उपकरण (Data Collection Tools)

प्रश्नावली (Questionnaire): उत्तरदाताओं के लिए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई, जिसमें 'शराबबंदी', 'नकद प्रोत्साहन' और 'मतदान प्राथमिकता' जैसे बंद और खुले प्रश्न शामिल थे।

फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD): जीविका समूहों के साथ 15 सामूहिक चर्चाएं आयोजित की गईं ताकि यह समझा जा सके कि ₹10,000 की राशि ने उनके सामूहिक राजनीतिक निर्णय को कैसे प्रभावित किया।

4) डेटा विश्लेषण की तकनीक (Data Analysis Techniques)

संग्रहीत डेटा का विश्लेषण SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) के माध्यम से किया गया है।

- **प्रतिगमन विश्लेषण (Regression Analysis):** यह जांचने के लिए कि "नकद लाभ" (Independent Variable) और "सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान" (Dependent Variable) के बीच कितना मजबूत संबंध है।
- **तुलनात्मक चार्ट्स:** 2020 बनाम 2025 के महिला मतदान व्यवहार के अंतर को प्रदर्शित करने के लिए।

5) **नैतिक विचार (Ethical Considerations)**

शोध के दौरान सभी उत्तरदाताओं की गोपनीयता (Confidentiality) का पूर्ण ध्यान रखा गया है और उनकी सहमति (Informed Consent) के बाद ही डेटा का उपयोग किया गया है।

मुख्य विश्लेषण (MAIN ANALYSIS)

जीविका समूहों का राजनीतिकरण और 'नकद-आधारित लामबंदी' (Cash-based Mobilization)

बिहार में 'जीविका' (BRLPS) की शुरुआत मूलतः एक गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन परियोजना के रूप में हुई थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों तक यह राज्य का सबसे बड़ा 'राजनीतिक नेटवर्क' बन गया है। इस विश्लेषण का मुख्य केंद्र वह प्रोत्साहन राशि है जिसे चुनाव से ठीक पहले वितरित किया गया।

₹10,000 की प्रोत्साहन राशि और 'कृतज्ञता का अर्थशास्त्र' (Economics of Gratitude)

शोध के दौरान यह पाया गया कि प्रत्येक जीविका दीदी को दी गई ₹10,000 की राशि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तत्काल तरलता (Liquidity) पैदा की। अकादमिक दृष्टिकोण से, इसे 'रेसिप्रोसिटी थ्योरी' (Reciprocity Theory) के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ राज्य द्वारा दिया गया आर्थिक लाभ मतदाता के भीतर एक नैतिक जवाबदेही या 'कृतज्ञता' का भाव पैदा करता है।

सर्वेक्षण के आंकड़ों (SAMPLE SIZE: 800 जीविका दीदियां) के अनुसार

- 82% महिलाओं ने स्वीकार किया कि चुनाव से पहले मिली राशि ने उनके परिवार के वोट देने के निर्णय को प्रभावित किया।
- 65% महिलाओं ने माना कि वे इस राशि को मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत 'उपहार' के रूप में देखती हैं, न कि किसी प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में।

सांगठनिक शक्ति और बूथ प्रबंधन (Organizational Power and Booth Management)

जीविका समूह केवल आर्थिक इकाइयां नहीं रह गई हैं। 2025 के चुनावों में, इन समूहों ने अनौपचारिक 'कैनवासिंग' (Canvassing) एजेंटों के रूप में कार्य किया। चूंकि एक जीविका दीदी अपने समूह की 10-15 अन्य महिलाओं के साथ निरंतर संपर्क में रहती है, इसलिए राजनीतिक संदेश का प्रसार बहुत तीव्र रहा।

डेटा विश्लेषण: जीविका घनत्व बनाम वोट शेयर

नीचे दी गई तालिका दर्शाती है कि जिन क्षेत्रों में जीविका समूहों की संख्या अधिक थी, वहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन (NDA) के वोट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई:

जिला श्रेणी	जीविका समूहों की संख्या (औसत)	महिला मतदान प्रतिशत (2025)	सत्तारूढ़ दल का वोट शेयर (%)
उच्च घनत्व (उदा. गया, मुजफ्फरपुर)	45,000+	74.2%	52.8%
मध्यम घनत्व (उदा. वैशाली)	25,000 - 40,000	68.5%	46.2%
कम घनत्व (उदा. पटना शहरी)	15,000 से कम	61.3%	41.5%

(स्रोत: संकलित डेटा आधारित ECI 2025 एवं BRLPS रिपोर्ट 2025)

उच्च शिक्षा और प्रोत्साहन राशियाँ (कन्या उत्थान योजना)

बिहार में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए नकद प्रोत्साहन का मॉडल न केवल शैक्षिक सुधार का साधन बना है, बल्कि इसने एक 'लॉयल यंग वोट बैंक' (Loyal Young Vote Bank) भी तैयार किया है। इस उपखंड में हम स्नातक छात्राओं को मिलने वाली ₹50,000 की राशि और उसके चुनावी प्रभाव का विश्लेषण करेंगे।

कन्या उत्थान योजना: आर्थिक सुरक्षा और स्वावलंबन

'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत स्नातक उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित छात्राओं को दी जाने वाली ₹50,000 की एकमुश्त राशि (DBT के माध्यम से) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की छात्राओं के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत साबित हुई है।

सांख्यिकीय डेटा (2025): बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस मद में ₹700 करोड़ की राशि चुनाव से ठीक पहले जारी की, जिससे लगभग 1.40 लाख स्नातक छात्राओं को सीधा लाभ पहुँचा LiveHindustan (2025)।

प्रभाव: सर्वे में शामिल 400 स्नातक छात्राओं में से 78% ने माना कि इस राशि ने उनकी आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं (BPSC, SSC) की तैयारी में वित्तीय बाधा को दूर किया, जिससे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में 'नीति-समर्थक' सकारात्मकता आई।

शैक्षिक प्रोत्साहन बनाम चुनावी प्राथमिकता

अकादमिक रूप से इसे 'इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल' के रूप में देखा जाता है, लेकिन चुनावी राजनीति में यह 'क्रेडिट क्लेमिंग' (Credit Claiming) का उत्कृष्ट उदाहरण है। 2025 के विधानसभा चुनावों में पहली बार वोट देने वाली महिला मतदाताओं (First-time Voters) के बीच इस योजना की लोकप्रियता सर्वाधिक रही।

योजनाओं का तुलनात्मक प्रभाव विश्लेषण (2025 चुनाव)

योजना का नाम	लक्षित समूह	प्रोत्साहन राशि	चुनावी प्रभाव (महिला प्रतिक्रिया)
इंटरमीडिएट प्रोत्साहन	12वीं पास छात्राएं	₹25,000	मध्यम (पारिवारिक निर्णय आधारित)
स्नातक प्रोत्साहन	स्नातक पास छात्राएं	₹50,000	उच्च (स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय)
पोशाक एवं साइकिल	स्कूली छात्राएं	विभिन्न	स्थिर (दीर्घकालिक निष्ठा)

(स्रोत: संकलित फील्ड सर्वे डेटा एवं शिक्षा विभाग, बिहार रिपोर्ट 2025)

'जेनरेशन शिफ्ट' और राजनीतिक चेतना

उच्च शिक्षा के लिए मिल रही इस राशि ने युवा महिलाओं के भीतर 'एजेंसी' (Agency) का भाव विकसित किया है। स्नातक छात्राओं ने 2025 चुनाव में न केवल स्वयं मतदान किया, बल्कि अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के पारंपरिक मतदान पैटर्न को भी चुनौती दी। इसे 'एजुकेशन-लेड पोलिटिकल मोबिलाइजेशन' कहा जा सकता है।

शराबबंदी: सामाजिक सुधार बनाम चुनावी सुरक्षा कवच

बिहार में 2016 से लागू पूर्ण शराबबंदी केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के 'नारी-केंद्रित शासन' (Women-centric Governance) का आधारस्तंभ रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, इस नीति ने सत्ताधारी दल के लिए एक ऐसे 'अभेद्य सुरक्षा कवच' के रूप में कार्य किया, जिसने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की धार को कम कर दिया।

सुरक्षा का बोध और 'रक्षक' की छवि

शराबबंदी का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण महिलाओं की असुरक्षा की भावना को कम करना रहा है। शोध के दौरान यह पाया गया कि शराबबंदी के कानूनी कार्यान्वयन में खामियों के बावजूद, महिला मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इसे मुख्यमंत्री के 'साहसी निर्णय' के रूप में देखता है।

सांख्यिकी (NFHS-5 एवं फील्ड सर्वे 2025): सर्वे में शामिल 89% महिलाओं ने माना कि शराबबंदी के बाद उनके घरों में 'शांति' आई है और घरेलू हिंसा की घटनाओं में (विशेष रूप से शारीरिक शोषण में) 35% की कमी महसूस की गई है **Ideas for India (2023, NFHS-5 (2021)**।

चुनावी प्रभाव: चुनाव के समय जब विपक्षी दलों ने शराबबंदी की विफलता और अवैध शराब (Hooch) की घटनाओं को मुद्दा बनाया, तब महिलाओं ने इसे 'पुरुषों का तर्क' मानकर खारिज कर दिया और सरकार के पक्ष में खड़ी रहीं।

पारिवारिक अर्थव्यवस्था का प्रबंधन

अकादमिक विश्लेषण यह दर्शाता है कि शराबबंदी ने 'गरीबों की डिस्पोजेबल आय' (Disposable Income) को बढ़ा दिया है। जो पैसा पहले शराब पर खर्च होता था, वह अब बच्चों की शिक्षा, बेहतर भोजन और जीविका समूहों की किस्तों को चुकाने में जा रहा है।

डेटा विश्लेषण: जीविका दीदियों के बीच किए गए सर्वे (Sample: 800) में पाया गया कि शराबबंदी के बाद प्रति परिवार मासिक बचत में औसत ₹1,500 से ₹2,500 की वृद्धि हुई है।

'वोट बैंक' की स्थिरता (Loyalty Factor)

2025 के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि शराबबंदी ने 'क्रॉस-कास्ट' (Cross-caste) वोटिंग को बढ़ावा दिया। कई महिला मतदाताओं ने अपने पुरुष सदस्यों की जाति-आधारित प्राथमिकताओं को दरकिनार करते हुए 'शराबबंदी' के समर्थन में मतदान किया। इसे राजनीति विज्ञान में 'प्रोटेक्शनिस्ट वोटिंग' (Protectionist Voting) कहा जाता है।

शराबबंदी का प्रभाव: एक नजर में (2025 सर्वे डेटा)

प्रभाव क्षेत्र	सकारात्मक प्रतिक्रिया (%)	प्रमुख तर्क
सामाजिक प्रतिष्ठा	92%	शराबियों द्वारा सार्वजनिक उपद्रव में कमी।
आर्थिक स्थिति	76%	घरेलू खर्चों के लिए अधिक धन की उपलब्धता।
राजनीतिक निष्ठा	81%	"नीतीश कुमार ने हमारी बात सुनी, इसलिए हम उनके साथ हैं।"

आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य: 'अदृश्य' लागत

जहाँ महिला मतदाता इसे सुरक्षा कवच मानती हैं, वहीं शोध का एक हिस्सा यह भी उजागर करता है कि शराबबंदी के कारण दलित और अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBC) के पुरुषों की गिरफ्तारी ने महिलाओं पर आर्थिक बोझ भी बढ़ाया है। कानून के दुरुपयोग ने एक नया 'न्यायिक संकट' पैदा किया है, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से यह महिलाओं के समर्थन के सामने गौण रहा।

तुलनात्मक विश्लेषण: 2010 से 2025 तक महिला मतदान का उभरता ग्राफ

यह खंड इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि बिहार में महिलाओं का बढ़ता मतदान प्रतिशत कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सुविचारित सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन का परिणाम है।

मतदान प्रतिशत में ऐतिहासिक वृद्धि (Gender-wise Turnout Gap)

निर्वाचन आयोग (ECI) के डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 2010 के बाद से महिलाओं ने मतदान के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ना शुरू किया। 2025 के चुनावों ने इस अंतर (Gender Gap) को अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुँचा दिया है।

चुनाव वर्ष	महिला मतदान (%)	पुरुष मतदान (%)	जेंडर गैप (महिलाओं की बढ़त)
2010	54.49%	51.12%	+3.37%
2015	60.48%	53.32%	+7.16%
2020	59.99%	54.68%	+5.31%
2025	71.60%	62.80%	+8.80%
(स्रोत: संकलित डेटा आधारित ECI रिपोर्ट्स 2010-2025)			

ट्रेंड का विश्लेषण (Trend Analysis)

1) **2010 (आरंभिक प्रभाव):** यह वह दौर था जब 50% पंचायत आरक्षण और साइकिल योजना का प्रभाव जमीन पर दिखना शुरू हुआ था।
2) **2015 (स्थिरीकरण):** महिलाओं ने स्वयं को एक निर्णायक 'वोट ब्लॉक' के रूप में स्थापित किया।
3) **2020 (संकट और विश्वास):** कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा, जो 'जीविका' जैसे समूहों के संगठनात्मक ढांचे की मजबूती को दर्शाता है।
4) **2025 (चरम सशक्तिकरण):** जीविका दीदियों को मिली ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि और शराबबंदी के प्रति अटूट समर्थन ने मतदान प्रतिशत को 71.6% के जादुई आंकड़े तक पहुँचा दिया।

सीटवार स्ट्राइक रेट और महिला प्राथमिकता

डेटा यह भी स्पष्ट करता है कि जिन सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 5% से अधिक मतदान किया, वहाँ सत्तारूढ़ दल (NDA) का स्ट्राइक रेट 75% से अधिक रहा है। यह सिद्ध करता है कि "महिला राजनीति के नए आयाम" अब केवल मतदान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे यह तय कर रहे हैं कि राज्य की सत्ता की चाबी किसके पास होगी।

चुनौतियां और आलोचना (CHALLENGES AND CRITICISM)

यद्यपि जीविका समूहों और शराबबंदी ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से लामबंद किया है, किंतु इसके कार्यान्वयन और दीर्घकालिक प्रभावों पर विद्वानों ने निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं:

शराबबंदी का 'अंधेरा पक्ष': प्रशासनिक विफलता और माफिया राज

शराबबंदी का सबसे बड़ा आलोच्य बिंदु इसका प्रभावी कार्यान्वयन (Implementation) न हो पाना है।

अवैध अर्थव्यवस्था का उदय: शोध बताते हैं कि राज्य में शराबबंदी के बाद एक समानांतर 'ब्लैक इकोनॉमी' विकसित हुई है। इस अध्ययन के अनुसार, शराब अब 'होम डिलीवरी' के माध्यम से अधिक कीमतों पर उपलब्ध है, जिसका आर्थिक बोझ अंततः गरीब परिवारों की महिलाओं पर ही पड़ रहा है।

न्यायिक बोझ: पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार, शराबबंदी कानून से संबंधित मुकदमों ने अदालतों पर भारी दबाव डाला है, जिससे अन्य गंभीर अपराधों की सुनवाई में देरी हो रही है Patna High Court. (2024)।

'नकद बनाम सशक्तिकरण' (Cash vs Empowerment) का द्वंद्व

2025 के चुनाव में जीविका दीदियों को दी गई ₹10,000 की राशि और छात्राओं को मिलने वाले नकद प्रोत्साहन को कई आलोचक 'चुनावी रिश्वत' (Electoral Bribery) के रूप में देखते हैं।

सांप्रदायिक और जातिगत ध्रुवीकरण: आलोचकों का तर्क है कि ये योजनाएं महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाने के बजाय उन्हें 'उपभोक्ता' बना रही हैं। मिश्रा (2024) का तर्क है कि जब तक महिलाओं को राजनीतिक दलों में टिकट वितरण और नीति निर्माण के शीर्ष पदों पर जगह नहीं मिलती, तब तक नकद प्रोत्साहन केवल एक 'वोट-खरीदने' की तकनीक बना रहेगा।

सामाजिक लागत: अति-पिछड़ों और दलितों का अपराधीकरण

शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार होने वाले लोगों में एक बड़ा हिस्सा समाज के सबसे गरीब तबके (SC/ST और EBC) का है।

महिलाओं पर दोहरा बोझ: जब घर का कमाऊ पुरुष सदस्य शराबबंदी के तहत जेल जाता है, तो परिवार को कानूनी लड़ाई और जीविका चलाने का दोहरा बोझ महिला पर ही आता है। साक्षी (2025) ने रेखांकित किया है कि हज़ारों गरीब महिलाएं आज अपने पतियों को जेल से छुड़ाने के लिए कर्ज़ के जाल में फंस चुकी हैं।

जीविका समूहों का 'राजनीतिकरण'

जीविका (JEEViKA) समूहों का उपयोग जिस प्रकार चुनावी मशीनरी के रूप में किया जा रहा है, उससे इसकी मूल भावना (वित्तीय समावेशन) को खतरा पैदा हो गया है। सरकारी मशीनरी द्वारा जीविका दीदियों पर एक खास दल के पक्ष में माहौल बनाने का दबाव इसके गैर-राजनीतिक (Non-political) चरित्र को नष्ट कर रहा है।

निष्कर्ष (CONCLUSION)

प्रस्तुत शोध का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि बिहार की राजनीति में 'महिला मतदाता' अब कोई मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक संगठित और निर्णायक राजनीतिक शक्ति बन चुकी हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों के परिणाम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि शराबबंदी, जीविका समूहों का सशक्तिकरण और नकद प्रोत्साहन योजनाओं (साइकिल, पोशाक, स्नातक छात्रवृत्ति) ने मिलकर एक 'सुरक्षात्मक और हितकारी राज्य' (Protective and Benefactor State) की छवि निर्मित की है।

इस शोध के मुख्य निष्कर्षों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:

1) **स्वतंत्र राजनीतिक एजेंसी का उदय:** बिहार में महिलाओं ने जातिगत बंधनों से ऊपर उठकर 'लिंग-आधारित लामबंदी' का परिचय दिया है। 2025 में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का 8.80% अधिक मतदान करना यह सिद्ध करता है कि वे अब स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय ले रही हैं।
2) **आर्थिक प्रोत्साहन और चुनावी वफादारी:** जीविका दीदियों को वितरित ₹10,000 की राशि और स्नातक छात्राओं को दी गई प्रोत्साहन राशि ने 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (DBT) को चुनावी जीत के सबसे प्रभावी हथियार के रूप में स्थापित किया है। इसे 'कृतज्ञता के अर्थशास्त्र' के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ राज्य द्वारा किया गया निवेश चुनावी समर्थन में परिवर्तित हो रहा है।
3) **शराबबंदी:** एक सामाजिक सुरक्षा कवच: तमाम प्रशासनिक खामियों और अवैध शराब की चुनौतियों के बावजूद, ग्रामीण महिलाओं के लिए शराबबंदी आज भी मान-मर्यादा और घरेलू शांति का प्रतीक है। यही कारण है कि यह नीति चुनाव में सत्ताधारी दल के लिए एक 'फायरवॉल' की तरह काम करती है।

चुनौतियां और भविष्य की राह: यद्यपि ये नीतियां चुनावी दृष्टिकोण से सफल रही हैं, किंतु इनका वास्तविक सामाजिक प्रभाव अभी भी जांच के घेरे में है। शराबबंदी के कारण दलितों और पिछड़ों का बढ़ता अपराधीकरण और महिलाओं की 'प्रतीकात्मक भागीदारी' गंभीर चिंता का विषय है। केवल नकद बांटना सशक्तिकरण का अंतिम पैमाना नहीं हो सकता। भविष्य में बिहार की राजनीति को 'लोक-लुभावनवाद' (Populism) से आगे बढ़कर 'समान भागीदारी' (Substantive Representation) की ओर बढ़ना होगा, जहाँ महिलाएं केवल लाभार्थी (Beneficiaries) न होकर नीति-निर्माता (Policy Makers) भी बनें।

अंततः, बिहार का यह 'महिला मॉडल' भारतीय राजनीति के लिए एक प्रयोगशाला है, जो यह दिखाता है कि यदि राज्य सामाजिक सुधारों को चुनावी राजनीति के साथ चतुराई से जोड़ दे, तो वह पारंपरिक जातिगत समीकरणों को भी ध्वस्त कर सकता है।

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Ahmed, S. (2022). Liquor Mafia and State Capacity: A Study of Bihar's Prohibition Policy. Journal of Social Dynamics, 14(2), 45–62.
Bihar Education Department. (2025). Status Report on Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana (10–25). Government of Bihar.
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS). (2025). Annual progress Report: Expanding Financial Inclusion Through Jeevika (102–118).
CSDS–Lokniti. (2025). Decoding the Bihar Mandate: The Women Factor (National Election Study 2025, (5–18). New Delhi.
Creswell, J. W. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed., pp. 210–235). Sage Publications.
Datta, S. (2015). A Sociological Analysis of Jeevika in Rural Bihar. World Bank Policy Research Paper, 34–50.
Deshpande, R. (2019). Gender and Politics in India: New Dimensions (88–104). Sage Publications.
Dreze, J., and Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and its Contradictions (Chapter on Bihar, 156–180). Penguin Books.
Election Commission of India. (2020 & 2025). Statistical Report on General Election to the Legislative Assembly of Bihar. ECI Publications.

Gupta, M. (2024). Prohibition and the Informal Economy in Bihar. Indian Economic Journal, 72(1), 12–28.
Ideas for India. (2023). Impact of Bihar's Alcohol Ban on Intimate Partner violence. I4I Evidence-Based Policy Portal.
Jaffrelot, C., and Verniers, G. (2020). The Reconfiguration of Indian Politics: Bihar as a Case Study (245–270). Oxford University Press.
Jha, M. (2025). The Economics of Gratitude: How Cash Transfers Influence rural women's vote. Indian Journal of Political Science, 86(3), 312–325.
Kothari, C. R. (2024). Research methodology: Methods and techniques (115–140). New Age International.
Kumar, S. (2018). Caste and Voting Behavior in Bihar (55–78). Routledge.
Kumar, S. (2025). Women as an Independent Vote Bank: The 2025 Bihar Phenomenon (CSDS–Lokniti Occasional Paper,1–22).
Mishra, N. (2024). The JEEViKA Factor: How Microfinance Transformed into Political Capital. Journal of Rural Development, 43, 90–112.
National Family Health Survey (NFHS-5). (2021). Bihar State Report (400–450). Ministry of Health and Family Welfare.
Patna High Court. (2024). Annual Report on Liquor Prohibition Cases and Judicial Burden (15–22). Legal Statistics Cell.
Pradhan, A. (2021). Self-help Groups and Women's Empowerment in Bihar. International Journal of Gender Studies, 67–84.
Prasad, R. (2025). Nitish Kumar's Masterstroke: Analysis of the ₹10,000 grant to Jeevika Didis. Economic Times Special Report, 4–6.
Sakshi, M. (2025). Examining the Unintended Consequences of Bihar's Alcohol ban. ATSK Journal of Sociology, 9(1), 130–145.
Singh, R. (2016). Prohibition as a poll promise: The gender factor in Bihar elections. Economic & Political Weekly, 51, 12–15.
Sinha, V. (2025). Electoral Geographies of Prohibition: How the Women of Bihar Reshaped the Mandate (210–230). Routledge India.
World Bank. (2015/2024). Recasting Culture to Undo Gender: Impact Evaluation of Jeevika (45–70). World Bank Group.
Zumbish, A. (2019). The Silent Revolution: Women Voters in Modern Bihar (180–205). Oxford University Press.